



संपूर्ण भारत के
लिए एक प्रकाशन

घट्टीघट्टा

लेख एवं विचार अभिव्यक्ति

अम्बिकापुर, रविवार 08 सितम्बर 2024

2

खुला पत्र

दैनिक
घट्टीघट्टा
कलम बंद

सरकार

प्रकाशन

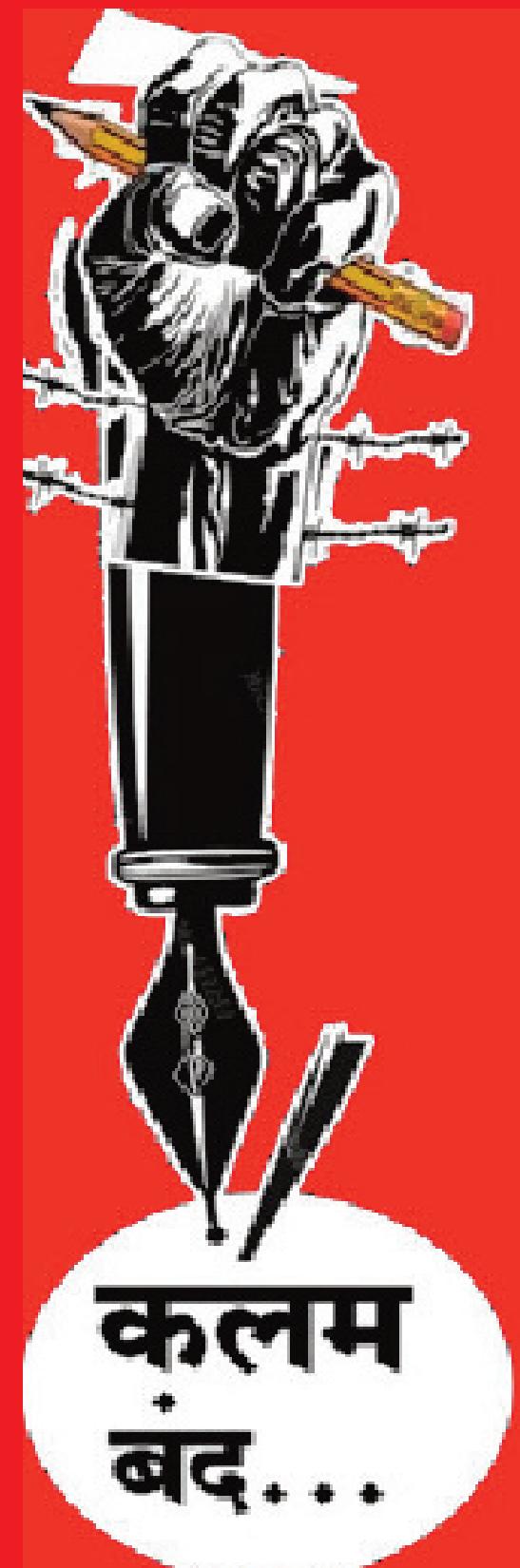
कुगलकी फरमान के विरुद्ध कलमबंद अभियान का...68 वां दिन



कलम
बंद...



कलम
बंद...का
68 वां
दिन



कलम
बंद...

कलमबंद से घट्टी-घट्टा के स्थही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अंदर होगा।

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

C M Y K

**उत्तीसगढ़ जैसी बुलडोजर कार्यवाही शायद ही देखी होगी...
कार्यवाही किसी आतंकवादी, हत्यारे या बलात्कारी के विरुद्ध नहीं
अखबार के दफ्तर प्रतिष्ठान के विरुद्ध....**

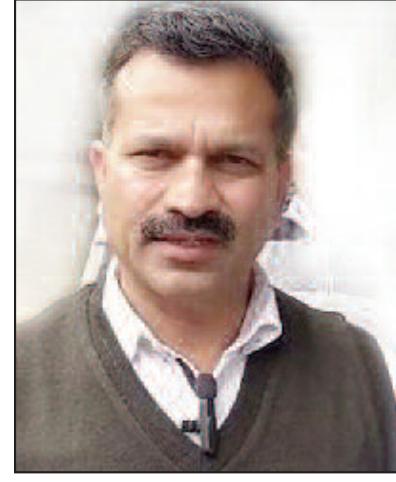
- » कसूर तो बस अखबार के संपादक व पत्रकार का इतना ही था कि वर्तमान सरकार की कमियों को दिखा रहा था
- » अखबार के दफ्तर पर तो कार्यवाही हो गई पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र व फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही से क्यों घबरा रही शासन ?
- » अखबार तो खबर प्रकाशित कर सरकार को वह कमियाँ दिख रहा था जिसे दूर करके जनता की हितेषी सरकार बनी...पर क्या वह जनता की हितेषी नहीं बनना चाह रही ?
- » अखबार के दफ्तर पर कार्यवाही करने से तो शासन नहीं घबराई

पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र व फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले संजय व प्रिंस पर कार्यवाही करने से घबराहट क्यों ?

» जिस अखबार को लोग छोटा अखबार मानते हैं आखिर इस अखबार की खबर से बौखलाहट क्यों होती है ?

» सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान ने प्रतिष्ठान व कार्यालय पर बुलडोजर किसके हुक्म पर चलवाया ?

» अखबार के कलम बंद करने से लेकर अखबार के कार्यालय व संपादक के प्रतिष्ठान के टूटने तक की कहानी अपनी जुबानी...



- भूपन्द्र सिंह -
अंबिकापुर, 07 सितंबर 2024
(घटती-घटना)।

- भूपन्न सिंह-
अंबिकापुर, 07 सितंबर 2024
(घटती-घटना)।

पूरे देश में अपने बुलडोजर कार्यवाही के कई मामले देखे व सुने होंगे लगभग सभी मामले ऐसे प्रकरणों में देखने व सुनने को मिले होंगे जो मामले आतंकवादी या हत्यारे या फिर बलात्कारी व भू माफियों से जुड़े होते हैं, जो काफी कूरता पूर्वक किसी अपराध को अंजाम देते हैं इसके प्रति जनता में काफी विरोध होता है और सरकार से न्याय की उमीद होती है, ऐसी कार्यवाहियों पर जनता भी सरकार की पीठ थपथपाने का प्रयास करती है, पर इस समय देश के एक छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ की एक बुलडोजर कार्यवाही की बात हो रही है जो अपने आप में एक अजीबो-गरीब कार्यवाही कहीं जा सकती है, यह कार्यवाही कहे तो लोकतंत्र के विरुद्ध है कहे तो लोकतंत्र के चौथे स्तर्भ को दबाने के लिए है या कहे तो पावर वाले व्यक्तियों के लिए है जो सच प्रशासन बर्दाश्ट नहीं कर सकते? यह कार्यवाही आतंकवादी हत्यारे व बलात्कारियों के विरुद्ध नहीं हुई यह कार्यवाही हुई तो लोकतंत्र के चौथे स्तर्भ व सर्वधान के अनुच्छेद 19 के तहत ईमानदारी से खबर प्रकाशित करने वाले अखबार के दफ्तर के विरुद्ध हुई, उसके प्रतिश्वाके विरुद्ध हुई,

स्तंभ को दबाने के लिए है या कहं तो पावर वाले व्यक्तियों के लिए है जो सच प्रशासन बर्दाश्ट नहीं कर सकते? यह कार्यवाही आतंकवादी हत्यारे व बलात्कारियों के विरुद्ध नहीं हुई यह कार्यवाही हुई तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ व संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ईमानदारी से खबर प्रकाशित करने वाले अखबार के दफ्तर के विरुद्ध हुई, उसके प्रतिष्ठा के विरुद्ध हुई,

दैनिक घटती-घटना संस्थान पर **बुलडोजर चलाकर** क्या कूरतावादी होने का परिचय दिया सरकार ने?

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के दैनिक घटती-घटना अखबार को आखिरकार कलम बंद वर्यों करना पड़ा... ?
यह सवाल सभी के जेहन में आ रहा होगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि दैनिक घटती-घटना अखबार सदैव ही लोगों के लिए सच्ची खबरें प्रकाशित करने का काम करता है, सरकार किसी की भी हो उन्हें कमियां दिखाने का काम करता रहा है, वर्तमान सरकार में कमियों को दिखाने का काम एक बार फिर दैनिक घटती-घटना ने शुरू किया जिसका परिणाम यह मिला कि कार्यालय व प्रतिष्ठान को जर्मांदोज कर दिया। कलेक्टर सरगुजा को वैसे तो काफी ईमानदार छवि का माना जा रहा था जब वह सरगुजा पहुंचे थे कलेक्टर बनकर लेंकिन जैसे ही उनका नाम प्रधारी डीपीएम प्रिंस के जायसवाल से जुड़ा वैसे ही उनकी भी छवि अब पाक-साफ नहीं रह गई। यह माना जा सकता है। एक फर्जी अहर्ता के आधार पर नौकरी करने के आरोपी के साथ उनकी घनिष्ठा उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। प्रधारी डीपीएम प्रिंस की तो आदत में ही छल और भ्रष्टाचार शुमार है वहीं जैसे ही उसकी शिकायत पर कलेक्टर सरगुजा एक अखबार के विरुद्ध सक्रिय हुए उसे नेस्तनाबूत करने के लिए यह तय हो गया की कलेक्टर सरगुजा खुद के विवेक से चलने की बजाए एक ऐसे व्यक्ति के इशारे पर काम कर रहे हैं जो फिलहाल जिस नौकरी में है उसके ही जांच की मांग हो रही है और उसके अहर्ता के भी फर्जी होने की बात कही जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप तो जो हैं वह हैं ही।

क्या कसूर मात्र फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र व फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले की खबर प्रकाशित करना था ?

के दिखाने पर उसे दूर नहीं करना चाहती? किसी अखबार के दफ्तर पर हुई कार्यवाही को लेकर तरह-तरह के सवाल हैं और सवाल हो भी तो क्या ना हो? क्या वर्तमान सरकार भी फर्जी लोगों को ही संरक्षण देना चाहता है, वास्तविक दिव्यांग सरकार से मिलने वाले लाभ से वचित हो रहे हैं पर वही फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र पर नौकरी पाकर वास्तविक दिव्यांगों के हाथों मारा जा रहा, जिसे लेकर दैनिक घटती-घटना ने खबर प्रकाशित कर रखा था, जिसमें संजय मरकाम जो प्रशासनिक राज्य सेवा के अधिकारी हैं साथ सर्वतमान में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी हैं अब इनके ऊपर आरोप है कि उनके दिव्यांग प्रमाण-पत्र ही फर्जी है जिसके आधार पर वह डिप्टी कलेक्टर बन हुए हैं वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे कहकर धूमने वाले सूरजन के प्रभारी डीपीएम प्रिंस जायसवाल जिनकी डिग्री ही फर्जी है, अब इन दोनों के मामले में खबर प्रकाशित की जा रही थी जिसके विरुद्ध शासन व प्रशासन को सँज्ञान लेकर जांच करके कार्यवाही करनी थी पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में बबराहट हुई, पर वहीं उनकी कमियों को प्रकाशित कर वाले अखबार के दफ्तर व प्रतिष्ठा पर कार्यवाही बुलडोजर के द्वारा कर दी अपने पाक साफ सरकार बताने में लगे हुए हैं। दोनों ही स्वास्थ्य मंत्री से जुहुए हैं पर स्वास्थ्य मंत्री इन दोनों के मामले में साफ कह रहे हैं कि प्रभारी डीपीएम मेरा कोई भतीजा नहीं है और जांच के लिए बात कही गई है, वह उनके ओएसडी के डिग्री फर्जी है यह बात उन्हें पता नहीं थी पर अब पता तो भी वह कार्यवाही नहीं कर पा रहे, आखिर यह दोनों व्यक्ति कितन प्रभावशील व्यक्ति हैं कि स्वास्थ्य मंत्री भी उनके सामने लाचार हैं? पर वह इन सब खबरों को प्रकाशित करने वाला अखबार ही कसूरवार हो गया?

मही त्यवहार रखती है.. ?
या गया क्योंकि वह सरकार के भण्डार को उजागर करने वाली सरकार के

यतकर्ता भी कोरिया से दूंढ़ लाए...

जिसके परिष्कार लातार जनवानताजा खेड़े छप रहे थे...सरुगु विद्रोह दबाव बनाया जा सके। यहां तक कि कलम बंद अभियान को भी बंद

संविधान विरोधी हुई कार्यवाही पर एक नजर...
जिसका न्यायालय में जवाब तो सबको देना होगा

- » प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो दैनिक घटती-घटना की खबरों की ही देन है उनसे जुड़ी कमियों को अखबार ने जब दिखाना शुरू किया तो उन्हें यह बात रास नहीं आई।
 - » स्वास्थ्य मंत्री के विभाग में जो हो रहा था उससे उनकी छवि खराब हो रही थी जिसे बताने का काम दैनिक घटती-घटना ने किया तो यह नहीं पता था कि उन्हें बताना कभी महंगा पड़ेगा।
 - » कमियां दूर करने के बजाय दैनिक घटती-घटना को दबाने के लिए उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए जून 2024 में शासकीय विज्ञापन पर रोक लगाया गया।
 - » विज्ञापन रोक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दबाब बनाने के फैसले के विरोध में दैनिक घटती-घटना ने 1 जुलाई 2024 से कलम बंद अभियान की शुरूआत की ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमेशा ही स्वतंत्रता के साथ काम कर सके।
 - » दैनिक घटती-घटना अखबार इस अभियान को सिर्फ अपने लिए शुरू नहीं किया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए इस अभियान को शुरू किया...।
 - » 3 जुलाई 2024 को टीएल मीटिंग में कलेक्टर साहब ने अपने घनिष्ठा प्रिंस जायसवाल के आवेदन को मंगाया और जांच के लिए आदेशित किया।
 - » 5 जुलाई 2024 को नमनाकला आरआई ने जांच प्रतिवेदन जांच करके सौंप दिया।
 - » 10 जुलाई 2024 को आबांटन/व्यवस्थापन समिति के द्वारा हमारे आबांटन/व्यवस्थापन प्रकरण को अपात्र घोषित कर दिया गया।
 - » 13 जुलाई 2024 को मंत्री जी के प्रतिनिधि मंडल संपादक के कार्यालय पहुंचे बातचीत हुई और चलते बने।
 - » 19 जुलाई 2024 को कैबिनेट की बैठक रखी गई और पूर्व सरकार के फ्री होल्ड व 152 प्रतिशत वाली योजना को निरस्त कर दिया गया, जिस कारण पुरे प्रदेश के लोगों को नुकसान हुआ जिसका खामियजा नगरी निकाय चुनाव में वर्तमान सरकार भुगतान पड़ सकता है।
 - » अखबार के कार्यालय को और संपादक के प्रतिष्ठान को तोड़ने के लिए 19 जुलाई 2024 को कैबिनेट की बैठक रखी गई।
 - » 23 जुलाई 2024 को पूर्व सरकार के 152 परसेंट व फ्री होल्ड योजना को निरस्त कर दिया गया...यह आदेश लोगों की जानकारी में 26 जुलाई 2024 को आया और 26 जुलाई को ही बेदखली का नोटिस 23 जुलाई 2024 की तिथि पर दिया गया।
 - » अखबार के संपादक को बेदखली का नोटिस पितृ शोक के दैशन मिला 26 जुलाई 2024 को शाम 6:45 बजे के बाद मिला और 27 जुलाई 2024 का समय दिया गया बेदखली का।
 - » पितृ शोक में रहने के बावजूद संपादक ने तकाल ही 26 जुलाई 2024 को संबंधित अधिकारी को बेदखली में खाली करने के लिए समय मांग गया पर समय न देकर 28 जुलाई 2024 को सुबह 5:00 बजे प्रशासन कई बुलडोजर व सुरक्षा के साथ पहुंच गया।
 - » कार्यवाही की एक दिन पहले 27 जुलाई 2024 को रात 10:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधिमंडल जिसमें उनके ओएसडी संजय मरकाम सहित चार अन्य लोग संपादक के घर बैठे रहे और मामले पर बात करते रहे।
 - » स्वास्थ्य मंत्री का प्रतिनिधिमंडल 4:00 तक संपादक के घर बैठ रहा और 5:00 बजे कार्यवाही करने पूरे प्रशासनिक अमला पहुंच गया।
 - » दैनिक घटती-घटना के कलम बंद अभियान को संज्ञान में लेने के बजाय उस अभियान को बंद करने के लिए 28 जुलाई 2024 अखबार के कार्यालय व संपादक के प्रतिष्ठान पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई।
 - » दैनिक घटती-घटना के कलमबंद अभियान के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री और संयुक्त संचालनालय जनसंपर्क के उपसंचालक मयंक श्रीवास्तव से शासकीय विज्ञापन बंद करने को लेकर सवाल पूछा कि आखिर क्या छापे जिससे आपको बुरा ना लगे?
 - » यह बात भी सरकार को नागवार गुजरी और सरकार ने और बड़ा कदम उठाया ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कुचला जा सके।
 - » कलमबंद अभियान के तहत 28 दिनों से प्रदेश के जिम्मेदार व प्रदेश की बेहतरी के लिए जिनके हाथों में कमान है उनसे सवाल किया गया पर वह सवाल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और 28 में दिन दैनिक घटती घटना के संस्थान पर बुलडोजर चलवा दिया।
 - » बुलडोजर चलवाना भले ही लोकतंत्र को कुचलने के लिए आसान लगा हो पर बुलडोजर चलने की आवाज भी पूरे देश में गूंज गई।
 - » पूरे देश में छत्तीसगढ़ सरकार की तानाशाही दिख गई, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास दिख गया, पर नहीं दिख सकी तो सरकार की संवेदनशीलता सरकार ने यह बता दिया कि उनके अंदर संवेदना बिल्कुल नहीं है।
 - » जिस समय कार्यवाही की गई वह समय संपादक के घर पर शोक का था पर शोक के समय में सरकार ने कार्यवाही करके हिंदूवादी पार्टी होने के दावे को भी झुकला दिया।
 - » अखबार जो कमियों को दिखा रहा था वह कमी वार्कइ में सरकार की छवि को खराब कर रही थी सरकार अखबार की खबरों पर संज्ञान लेकर अपनी छवि को बेहतर कर सकती थी।
 - » उनके मंत्री अपनी छवि को बेहतर कर सकते थे पर अपनी छवि बेहतर करने के बजाय अपनी छवि को और खराब करने का सरकार का प्रयास सरकार के लिए ही गले की फांस बन गई।



बलदोज़ कार्यालय से अकादम के शेहर से बिंदवानी पर्यावरण विभाग

जिस तरह दैनिक घटनी-घटना समाचार-पत्र के विरुद्ध द्वेषवश कार्यवाही सरकार ने की वह कार्यवाही कोई हिंदूवादी सरकार की कार्यवाही नहीं कही जा सकती...? क्योंकि कार्यवाही पीढ़ी पर बार जैसी थी वहीं कार्यवाही तब की गई जब समाचार-पत्र के संपादक गमगीन अवस्था में थे यदि कहा जाए सूतक काल में थे। वैसे कार्यवाही के संदर्भ में यह भी देखने को मिला की कार्यवाही के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि कैबिनेट की बैठक भी उहें करनी पड़ी जो यह साबित करने काफी है की सरकार प्रदेश की हिंदूवादी सरकार जो भ्रष्टचार के विरुद्ध खुद को एक बेहतर सरकार बतलाती है वह भ्रष्टचार और भ्रष्टचारियों को बचाने के लिए निम्न स्तरीय निर्णय लेने भी मजबूर हुई क्योंकि भ्रष्टचारी एक तरफ एक मंत्री का भतीजा भी है और वहीं उसी मंत्री का एक ओएसडी भी और दोनों ही की नौकरी भी फर्जी है डिग्री फर्जी है एक की नौकरी फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर लगी है।

वया भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए ही सरकार केवल सरकार की नजर में हमारा कसूर खबरों के मध्यम से कभी दिखाना था, वया सही में यही वजह थी इसलिए प्रतिष्ठान को नेस्तनाबूत करने का निर्णय नित्रियों के ईर्द-गिर्द रहने वाले भ्रष्ट एवं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ वह अभियान चला रहा होता है, जिनकी या तो डिग्री फर्जी है या फिर वह फर्जी फलत लोगों साथ ही भ्रष्टाचार के गरसे नौकरी में आए भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ही सरकार केवल सही व्यवहार रखती है।

बरों के मध्यम से कमी दिखाना था, क्या सही में यही बजह थी इसलिए प्रतिष्ठान को नेस्तनाबूत करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि वह सरकार के भ्रष्ट

दैनिक घटती-घटना अखबार के कार्यालय व प्रतिष्ठा पर कार्यवाही करने के लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने कैसे शिकायतकर्ता को ढूँढ़ कर लाया...वह भी जिसके विरुद्ध लगातार अनियमिताओं खबर छप रही थी...सरगुजा जिले में उनीं जिला बिल्डिंग एवं रेलवे से लंब रिहाया गया जिला बार्फ़ और अलगाव से अर्द्ध लाख लाख रुपये और इसके लिए लगातार लाख रुपये देने की आदेश दिए गए थे...जिला बिल्डिंग एवं रेलवे से लंब रिहाया गया है..? इमानदार और भ्रष्टाचार विरुद्ध सोच रखने वाले के खिलाफ़ ही सरकार क्या बड़यंत्र कर रही है...यह भी एक बड़ा सवाल है।

बुलडोजर कार्यवाही हुई भी तो उसके शिकायत पर...जिसकी खबर छप रही थी...शिकायतकर्ता भी कोरिया से ढूँढ़ लाए...

संपूर्ण भारत के
लिए एक प्रकाशन**घट्टी घट्टा**

अंतर्राष्ट्रीय-सरगुजा-समाचार

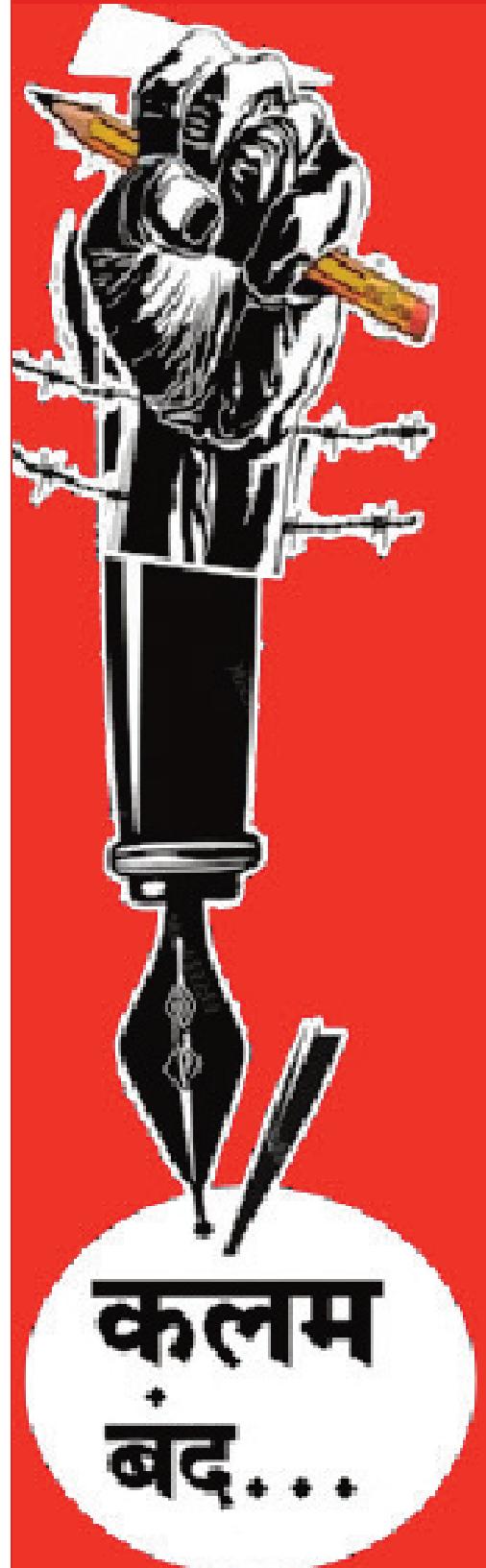
अम्बिकापुर, रविवार 08 सितम्बर 2024

4

खुला पत्र

**देश के माननीय प्रधानमंत्री से भी सवाल...क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध
छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार के खिलाफ समाचार लिखना है अपराध ?**

अम्बिकापुर, 07 सितम्बर 2024 (घट्टी-घट्टा) | माननीय मुख्यमंत्री से भी सवाल है...छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है...केंद्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है...पर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमियां दिखाने से रोकने का भी प्रयास हो रहा है...यह प्रयास कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास है...जहाँ पर भाजपा सरकार से लोगों को बेहतर करने की उम्मीद होती है तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित मंत्री, विधायक बे-लगाम हो चुके हैं...उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ दिख रहे हैं...उनकी कमियों को बताना उन्हें रास नहीं आ रहा इसलिए वह पत्रकार, संपादक का कलम बंद करने का प्रयास कर रहे हैं अब इस पर आप ही संज्ञान ले...और बताएं की संपादक व पत्रकार कौन सी खबर प्रकाशित करें ?

क्या छापें माननीय प्रधानमंत्री जी ?

कलम
बंद...का
68 वां
दिन



कलम
बंद...का
68 वां
दिन



कलमबंद से घट्टी-घट्टा के स्लेटी पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अकिलाश कुमार सिंह

खुला पत्र

भारत में सत्त्वे पत्रकार को राजनीतिक पार्टियों से खतरा क्यों रहता है?

अम्बिकापुर, 07 सितम्बर 2024(घट्टी-घट्टा)। भारत अपने पत्रकारों को निर छोड़कर काम करने का स्वतंत्र तरीका प्रदान करने में बहुत पीछे है...इन दिनों...कुछ को छोड़कर...हर दूसरा पत्रकार वही खबर दे रहा है जो सरकार की प्रशंसा करती है...नए चैनल लोगों को सरकार द्वारा की गई गलती से विवलित करने के लिए विभिन्न विषयों पर अनावश्यक बहस दिखाएंगे...इसके कारण, अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो किसी का ध्यान नहीं जाता है...दूसरा कारण यह है कि पत्रकार अपने सिद्धांतों और मूल्यों को खो रहे हैं क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि स्थापना के खिलाफ विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों को धमकी देना, गाली देना और मारना कई अन्य देशों की तरह भारत में भी एक वास्तविकता बन गई है...देश और दुनिया को डरा दिया है...वहीं, पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है...जो पत्रकार देश और उसके आम नागरिकों के लिए लिखे वे मरे या प्रताड़ित हुए सरकारी तंत्रों के द्वारा...!

अब आप ही पूछकर बताईए कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर साहब...कि क्या छापें?



कलम
बंद...का
68 वां
दिन



कलमबंद से घट्टी-घट्टा के सेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह



संपूर्ण भारत के
लिए एक प्रकाशन

घट्टी घट्टा

सूरजपुर-कोरबा-सरगुजा-समाचार

अम्बिकापुर, रविवार 08 सितम्बर 2024

6

खुला पत्र

क्या भ्रष्टाचार का मामला वहीं होगा दर्ज जहां होगी भाजपा से इतर दल की सरकार ?

» भ्रष्टाचार की खबरों से दिक्कत... » कर्मी दिखाओ तो दिक्कत...

» जनता की परेशानियों को दिखाओ तो दिक्कत...

अम्बिकापुर, 07 सितम्बर 2024(घट्टी-घट्टा)। आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करें तो क्या करें ? सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे भ्रष्टाचार को ऊआगर करने पत्रकार दौड़ रहा पर पत्रकार की दौड़ के पीछे निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसकी दौड़ की गति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता रहे पर पत्रकार ना दिखाएं क्या यही चाहता है जनप्रतिनिधि या फिर सरकारी तंत्र...

राष्ट्रपति महोदया, आखिर छापें क्या ?



कलम
बंद...का
68 वां
दिन



कलम
बंद...का
68 वां
दिन



कलमबंद से घट्टी-घट्टा के सेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभायितकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अदिनाय कुमार सिंह



तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलम बंद अभियान का 68 वां दिन

छत्तीसगढ़ सरकार बुलडोजर कार्यवाही झेलने के बावजूद... इंफलाब होता रहेगा इंसाफ तक...

क्या छापें कलेक्टर विलास भोसकर जी ?

ਕਿਸੁਂ ਨ ਲਿਖੇ ਸਕ ?

इमरजेंसी पर बात...हर बात पर आरोप...तो छत्तीसगढ़ में एक तुगलकी फरमान पर आदिवासी अंचल से विगत 20 वर्षों से प्रकाशित अखबार पर क्यों किया गया जुर्म...स्पष्टीकरण देना पड़ेगा?

क्यों कलमबंद आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा एक दैनिक अखबार को...?

कलमबंद से घटती-घटना के स्थेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह